

क्रांति समाय

सुविचारः— कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं !

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

मच्छगर पंचायत ने कोरोना राहत कोष में दिए १ करोड़

पृथला । सीएम कोरोना राहत कोष में गांव मच्छगर पंचायत ने एक करोड़ रुपये की राशि दी है। इस राशि का चेक गांव के सरपंच नरेश धनखड़ ने पृथला के विधायक एवं हरियाणा भंडारण निगम के अध्यक्ष नन्याना रावत को उनके निवास पर सौंपा। इस भौंके पर विधायक रावत ने कहा कि सरपंच ने एक सराहनीय पहल की है। वो इस चेक को उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री राहत कोष में पहुंचा देंगे। पृथला विधानसभा क्षेत्र की जनता ने लॉकडाउन की पूरी तरह से पालन की और शारीरिक दूरी बनाकर देश के प्रति अपना दायित्व निभाने का काम किया है। यह क्षेत्र में एक भी कोरोना पॉजिटिव मामला नहीं आया। अपने जिले में मच्छगर पहली ऐसी पंचायत है, जिसने इतनी बड़ी राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में दी है। इससे पृथला क्षेत्र का गौरव बढ़ गया है। इस अवसर पर पंचायत सचिव राजेश पाणशर मौजूद थे।

कोरोना के डर से लोग नहीं गए रमजान के पहले दिन मस्जिद

हथीन । मुस्लिम सम्मुदाय के लोग कोरोना वायरस के संक्रमण के डर और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए रमजान के पहले दिन मस्जिद नहीं गए। यहां तक कि रोजों के दौरान होने वाली विशेष नमाज भी मरिजदों में नहीं हुई। बताया गया कि रमजान से पूर्व मरिजदों को सजाने की जो परंपरा है, लेकिन उसका भी निर्वाह इस बार नहीं किया गया। गांव के निवासी सरफुद्दीन ने बताया कि सब लोग सरकार की हिदायतों का पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस्लाम के प्रति आस्था में कोई कमी नहीं है। मरिजदों के प्रति भी लागत है, लेकिन नाजुक दौर में घरों में बैठकर ही इबादत की जा रही है। गांव निवासी इदरीश और इलियास ने बताया कि आपातकाल में सावधानी जरूरी है। यही खित्ति मलाई, जलालपुर, भीमसीका, गुराकरस और खिलुका गांव की मरिजदों में रही। इस बारे में इलाके के मुस्लिम आलिम मुफ्ती लुकमान ने बताया कि इस्लामिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र देवबंद से भी इस विषय में आदेश

गुजरात में फंसे म. प्र. के ३ हजार मजदूरों की घर वापसी

इदौर, लॉक डाउन के दौरान गुजरात में फंसे मध्य प्रदेश के 3000 मजदूरों की वापसी कल हो गई। इनका झाबुआ बॉर्डर पर स्थान था। मुख्यमंत्री ने वसंत भेजकर उनकी घर वापसी की है। मजदूरों ने इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार माना है।

स्पेन, यूके और अमेरिका के बाद कनाडा के ओल्ड एज होम्स में हुई कोरोना संक्रमित बूढ़ों की मौत

मोट्रिल । कनाडा में भी हर दिन कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। यहां 44,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 2300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा में कोरोना से हुई मौतों में अधिकतर लोगों की उम्र 50 से ज्यादा है, जबकि इनमें से करीब 63 प्रतिशत लोग मोट्रिल और देश के अन्य शहरों में खित्ति ओल्ड एज होम्स में रह रहे थे। स्टाल उठ रहा है कि क्या इटली, स्पेन, यूके और अमेरिका के बाद यहां भी बूढ़ों को मरने के लिए छोड़ दिया गया था। कनाडा की राजधानी मोट्रिल में अभी तक कोरोना के सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। मोट्रिल के ओल्ड एज केयर होम में काम करने वाली महिला के मुताबिक उनके यहां रहने वाले सभी 180 बुजुर्गों कोरोना की चैपेट में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास अस्पतालों जैसी कोई राशि नहीं थी, हमारे पास मेडिकल इविंपेंट भी नहीं थी। इसकारण कोरोना संक्रमण ओल्ड एज होम्स में जंगल की आग की तरह फैल गया। बता दें कि कनाडा में ओल्ड एज होम्स को लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी के नाम से जाना जाता है। कनाडा के क्यूब्रेक शहर में हुई मौतों में से 97 प्रतिशत की उम्र 60 से ज्यादा है और इनमें से ज्यादातर ओल्ड एज होम्स में ही रह रहे थे।

कोरोना मुक्त हुए ८ राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश

नई दिल्ली । देशभर में अब ८ राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कोरोना मुक्त हो चुके हैं। इस लिस्ट में त्रिपुरा नया नाम है। त्रिपुरा के अलावा गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, दादर औंडा नागर हवेली और लक्ष्मीपैथ अब कोरोना फी हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में इस वायरस के संक्रमण से ठीक होने की दर (रिकवरी रेट) करीब 21 लाख १९० प्रतिशत है। कोरोना के खतरे के बीच यह थोड़ी राहत देने वाली खबर है। कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए ३ मई तक देशव्यापी लॉकडाउन जारी है।

आज कार्डने द्वाले द्वाले क्या कर्दाने ?

म.प्र. शासन का कोरोना से लड़ने और जीविका के संसाधन बढ़ाने हेतु अभिनव पहल – जीवन शक्ति योजना

उज्जैन । कोरोना वायरस से बचाव के लिए प्रदेश के नागरिकों को अधिकाधिक संख्या एवं कम कीमत में मास्क उपलब्ध कराने, और प्रदेश के शहरी क्षेत्रों की महिला उद्यमियों के रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के उद्देश से मध्य प्रदेश शासन द्वारा जीवन शक्ति योजना प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 25 अप्रैल 2020 को योजना की घोषणा करते हुए पोर्टल का शुभारंभ किया गया। योजना में शहरी क्षेत्रों में निवासरत महिला उद्यमी को पात्रता – प्रति मास्क 11 रु. के दर से भुगतान – महिला उद्यमियों द्वारा ऑनलाइन पंजीयन द्वारा आधार ने अथवा मोबाइल न के द्वारा – पंजीयन की सुविधा द्वारा संभव की गयी है।

प्रति मास्क 11 रु. के दर से भुगतान – महिला उद्यमियों द्वारा ऑनलाइन पंजीयन द्वारा आधार ने अथवा मोबाइल न के द्वारा – पंजीयन की सुविधा द्वारा संभव की गयी है।

योजना में शहरी क्षेत्रों में निवासरत महिला उद्यमी को पात्रता – प्रति मास्क 11 रु. के दर से भुगतान – महिला उद्यमियों द्वारा ऑनलाइन पंजीयन द्वारा आधार ने अथवा मोबाइल न के द्वारा – पंजीयन की सुविधा द्वारा संभव की गयी है।

योजना में शहरी क्षेत्रों में निवासरत महिला उद्यमी को पात्रता – प्रति मास्क 11 रु. के दर से भुगतान – महिला उद्यमियों द्वारा ऑनलाइन पंजीयन द्वारा आधार ने अथवा मोबाइल न के द्वारा – पंजीयन की सुविधा द्वारा संभव की गयी है।

योजना में शहरी क्षेत्रों में निवासरत महिला उद्यमी को पात्रता – प्रति मास्क 11 रु. के दर से भुगतान – महिला उद्यमियों द्वारा ऑनलाइन पंजीयन द्वारा आधार ने अथवा मोबाइल न के द्वारा – पंजीयन की सुविधा द्वारा संभव की गयी है।

योजना में शहरी क्षेत्रों में निवासरत महिला उद्यमी को पात्रता – प्रति मास्क 11 रु. के दर से भुगतान – महिला उद्यमियों द्वारा ऑनलाइन पंजीयन द्वारा आधार ने अथवा मोबाइल न के द्वारा – पंजीयन की सुविधा द्वारा संभव की गयी है।

योजना में शहरी क्षेत्रों में निवासरत महिला उद्यमी को पात्रता – प्रति मास्क 11 रु. के दर से भुगतान – महिला उद्यमियों द्वारा ऑनलाइन पंजीयन द्वारा आधार ने अथवा मोबाइल न के द्वारा – पंजीयन की सुविधा द्वारा संभव की गयी है।

योजना में शहरी क्षेत्रों में निवासरत महिला उद्यमी को पात्रता – प्रति मास्क 11 रु. के दर से भुगतान – महिला उद्यमियों द्वारा ऑनलाइन पंजीयन द्वारा आधार ने अथवा मोबाइल न के द्वारा – पंजीयन की सुविधा द्वारा संभव की गयी है।

योजना में शहरी क्षेत्रों में निवासरत महिला उद्यमी को पात्रता – प्रति मास्क 11 रु. के दर से भुगतान – महिला उद्यमियों द्वारा ऑनलाइन पंजीयन द्वारा आधार ने अथवा मोबाइल न के द्वारा – पंजीयन की सुविधा द्वारा संभव की गयी है।

योजना में शहरी क्षेत्रों में निवासरत महिला उद्यमी को पात्रता – प्रति मास्क 11 रु. के दर से भुगतान – महिला उद्यमियों द्वारा ऑनलाइन पंजीयन द्वारा आधार ने अथवा मोबाइल न के द्वारा – पंजीयन की सुविधा द्वारा संभव की गयी है।

योजना में शहरी क्षेत्रों में निवासरत महिला उद्यमी को पात्रता – प्रति मास्क 11 रु. के दर से भुगतान – महिला उद्यमियों द्वारा ऑनलाइन पंजीयन द्वारा आधार ने अथवा मोबाइल न के द्वारा – पंजीयन की सुविधा द्वारा संभव की गयी है।

योजना में शहरी क्षेत्रों में निवासरत महिला उद्यमी को पात्रता – प्रति मास्क 11 रु. के दर से भुगतान – महिला उद्यमियों द्वारा ऑनलाइन पंजीयन द्वारा आधार ने अथवा मोबाइल न के द्वारा – पंजीयन की सुविधा द्वारा संभव की गयी है।

योजना में शहरी क्षेत्रों में निवासरत महिला उद्यमी को पात्रता – प्रति मास्क 11 रु. के दर से भुगतान – महिला उद्यमियों द्वारा ऑनलाइन पंजीयन द्वारा आधार ने अथवा मोबाइल न के द्वारा – पंजीयन की सुविधा द्वारा संभव की गयी है।

योजना में शहरी क्षेत्रों में निवासरत महिला उद्यमी को पात्रता – प्रति मास्क 11 रु. के दर से भुगतान – महिला उद्यमियों द्वारा ऑनलाइन पंजीयन द्व



भारतीय संविधान में न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका का अलग अलग दायित्व है। मीडिया को स्वतंत्र को असीमित अधिकार मिला हुआ है। वैसा ही भारत में होना विशिष्ट वर्ग था। रखा गया था। वह जनता का प्रतिनिधित्व करें। इसके लिए चाहिए। उसे कोई अधिकार संविधान ने नहीं दिए।



केवल इतना अधिकार दिया, कि वह अपनी बात स्वतंत्रता से लिख सकता है, बोल सकता है। उसकी आवाज को जनता जनार्दन की आवाज माना जाएगा। पिछले कुछ समय से कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की कार्यप्रणाली को देखें, तो ऐसा लगता है, कि देश में जो भी हो रहा है। वह सब कार्यपालिका कर रही है। इसमें न्यायपालिका की भूमिका सरकार द्वारा किए गए कार्यों में अपनी सहमति प्रकट करना अथवा सरकार की सुविधानुसार निर्णय को टालना है।

इसी तरह विधायिका भी बड़े से बड़े मुद्दे में संसद और विधानसभाओं में कार्यपालिका के इशारे पर जितना बोलने की अनुमति दी जाती है। उतना ही सांसद और विधायक बोल पाते हैं। मीडिया की स्थिति भी कुछ इसी तरह की बन गई है। कार्यपालिका जो निर्देश देती है, मीडिया भी उसका अक्षरस पालन करना मजबूरी है। जिसके कारण देश में पहली बार कार्यपालिका की सर्वोच्चता देखने को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जब पदभार गृहण कर रहे थे। तब उन्होंने सरकार के साथ सहयोग करने की बात कही थी। लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभाओं में सत्ताधारी दल के सदस्य ही अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं। वह भी सरकार के कामकाज को सुगम बनाने का काम कर रहे हैं।

संसद और विधानसभाओं में सदस्यों को 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट में बड़े से बड़े मुद्दों पर अपनी बात कहनी होती है। संसद और विधानसभा के सत्रों की अवधि लगातार कम होती जा रही है। विवादास्पद मामलों में सत्ता पक्ष भी विपक्ष की तरह हंगामा करने का कोई मौका नहीं छोड़ता है।

जिसके कारण संसद और विधानसभाओं में भी कानूनों और नियमों को लेकर जैसा विचार विमर्श होना चाहिए, वैसा नहीं हो पाता है। जल्दबाजी एवं हंगामे के बीच में बिना किसी चर्चा के कार्यपालिका अपनी सुविधानुसार नियम कायदे कानून बनवाकर लागू कर देती है। जिसके कारण भारत जैसे देश में दूरगामी परिणामों को देखते हुए जिस तरह के निर्णय अथवा कानून विधायिका को बनाने चाहिए थे, वैसे कानून नहीं बन पा रहे हैं।

अब तो न्यायपालिका भी सरकार की मंशा को देखते हुए मामलों की सुनवाई कर रही है। हाल ही में वरिष्ठ अधिकारी हरीश साल्वे ने लिखा है, इस समय अदालतों को किसी भी हाल में कार्यपालिका को कार्य करने से नहीं रोकना चाहिए। उन्होंने

गरीबों और अमीरों के लिए भारत में दोहरे कानून?

तो यहां तक लिखा है, कि ब्रिटेन में जिस तरह कार्यपालिका को भारत बुलाया उनके लिए सारे इंतजाम किए। क्योंकि यह रखा गया था। वह जनता का प्रतिनिधित्व करें। इसके लिए चाहिए।

कोरोनावायरस के संक्रमण और आर्थिक आपदा को देखते हुए साल्वे का यह कथन काफी महत्वपूर्ण है। वहीं पिछले दिनों वरिष्ठ वकील दुष्ट दुबे ने लिखा है कि यह कैसा समय है। जब विधायिका और न्यायपालिका दोनों का काम लगता है, स्थगित हो गया है। सभी काम

की जवाबदारी केवल कार्यपालिका निभा रही है।

थे। वह वहीं फंसे रह गए।

पिछले वर्षों में जिस तरह से न्यायपालिका तथा विधायिका में कार्यपालिका का हस्तक्षेप बढ़ा है। सारी संवैधानिक संस्थाओं में कार्यपालिका का हस्तक्षेप प्रत्यक्ष देखने को मिल रहा है। हर संवैधानिक संस्थान कार्यपालिका के प्रत्येक निर्णय और कार्यों को आगे बढ़ाने में उसका सहयोग कर रहा है। उससे लगता है कि

प्रधानमंत्री के रूप में जो फैसला नरेंद्र मोदी जी लेते हैं। तीनों स्तंभ उसका पुरजोर समर्थन करने में लग जाते हैं। चौथा स्तंभ मीडिया भी अब इस मामले में पीछे नहीं रहा। भारत में सबसे ज्यादा भरोसा लोगों को न्यायपालिका के ऊपर था। न्यायपालिका संविधान को दृष्टिगत रखते हुए सरकार के बनाए हुए कानूनों नियमों के अनुसार लोगों के मौलिक अधिकार की समीक्षा करके स्वतंत्र निर्णय करती थी। उसे सारे लोग स्वीकार करते थे।



गरीबों के मामले में सरकार की सोच अलग है। गरीबों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोनावायरस के संक्रमण को देखते हुए जब लॉकडाउन की घोषणा की। तो केवल 4 घंटे का समय गरीबों को दिया। जिसके कारण करोड़ों मजदूर और गरीब जो अपना घर छोड़कर विभिन्न राज्यों में रोजी रोजगार और नौकरी के लिए गए



गए। उनमें कोई सुविधाएं नहीं हैं। वहां पर फिजिकल डिस्टेंस का भी पालन नहीं हो पारहा है।

उन्हें खाना भी नहीं मिल पा रहा



न्यायपालिका भी सरकार के किसी भी निर्णय पर उसकी संवैधानिक समीक्षा कर अवरोध बनाना नहीं चाहती है।

जिसके कारण पिछले वर्षों में अथवा पिछले माहों में न्यायपालिका ने जिस तरीके से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के साथ सहयोग किया है। उसको



लेकर अब यह कहा जाने लगा है, कि भारत में कार्यपालिका ही सर्वोच्च है।

न्यायपालिका और विधायिका कार्यपालिका के सामने बोने हैं। जिसके कारण भारत में अब जो है, वह सरकार ही है।

कोरोनावायरस संक्रमण के बाद जिस तरह की स्थितियां देश में देखने को मिल रही हैं। उसमें गरीब और अमीर की लड़ाई भी अब सामने दिखने लगी है। सरकार ने विदेशों से लोगों

कई वर्षों से सुप्रीम कोर्ट और अन्य संस्थाएं उनकी व्यथा सुनने के लिए तैयार नहीं हैं।

मॉकर्ट, हाईकोर्ट,

स्थिति यह बन गई है कि अब लोग कहने लगे हैं की

चुनाव आयोग,

जेल भेज देते,

तो वहां कम से कम दो टाइम का भोजन और

सीबीआई जैसी

रहने के लिए छत तो मिलती।

संस्थाएं, लोकस.

लेकिन क्वॉरेंटाइन सेंटर में जिस तरह से लोगों को

भा, राज्यसभा

बंद करके रखा है।

उससे तो अच्छे कांजी हाउस हैं।

जहां पर

के कामकाज

पशुओं को रखा जाता है।

है। सरकार का

प्रत्यक्ष हस्तक्षेप

एवं प्रभाव देखने

को मिल रहा है।

1 महीने से अधिक समय हो गया।

रोज कमाने खाने वाले

मजदूर और कामगार

आज अपने

प्रदर्शन के साथ

यहां से वहां भटक रहे हैं।

खाना नहीं मिल रहा है।

सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है।

विधायिका मौन साथे हुए बैठी है।

न्यायपालिका चुप है।

वह कह रही है, ऐसे समय पर हमें

सरकार का सहयोग करना है।

लेकिन गरीबों को सहयोग कौन करेगा। इसको लेकर कोई सोच नहीं है। जगह-जगह पर अब यह गरीब निकलकर,

अपना विरोध प्रदर्शन कर रहा है। उसे अभी भी

लगता है, कि सरकार और न्यायपालिका उसकी

बात सुनेगी।

उसे घर भेजने की व्यवस्था करेगी। क्वॉरेंटाइन

सेंटर्स की हालत सुधरेगी। अस्पतालों में इलाज

मिलेगा।

लेकिन अब उसका यह भरोसा भी धीरे-धीरे

टूटता चला जा रहा है। कहा जाता है, भूख

से बड़ी कोई आग नह

होमगार्ड को उठक-बैठक कराने वाले अधिकारी का हुआ प्रमोशन

पटना | बिहार के अररिया में होमगार्ड को उठक-बैठक कराने वाले जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार पर बिहार सरकार ने कार्रवाई करने के बजाए प्रमोशन दे दिया है। दरअसल, कुछ दिनों पहले अररिया में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्हें पुलिस विभाग में चौकीदार गणेश तत्मा को सजा के तौर पर उठक-बैठक करवाते देखा गया था। क्योंकि उसने लॉकडाउन के दौरान अपनी ड्यूटी करते वक्त उसने मनोज कुमार की गाड़ी को रोका था। इस बात पर कृषि पदाधिकारी इतना नाराज हो गए थे कि उन्होंने चौकीदार को जेल भेजने की धमकी दे डाली थी। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस विभाग ने मैके पर मौजूद एसएआई गोविंद सिंह को सस्पेंड कर दिया था क्योंकि उसने भी कृषि पदाधिकारी का ही साथ दिया है। अररिया में जांच प्रमाणित न हो, इसी वजह से उसे अब पदस्थापित करके मुख्यालय बुला लिया गया है। इस मामले में कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि मनोज कुमार पर कार्रवाई जारी रहेगी। सरकार ने सबसे पहले उसके खिलाफ अररिया में एफआईआर दर्ज करवाई है। अररिया में जांच प्रमाणित न हो, इसी वजह से उसे अब पदस्थापित करके मुख्यालय बुला लिया गया है।

बिहार में बिजली कर्मचारियों के वेतन पर गहराया संकट

पटना | कोरोना वायरस के वजह से लागू लॉकडाउन के कारण बिहार में सरकारी विभाग आर्थिक संकट से जुर्जर रहे हैं। इन्हीं विभागों में बिजली विभाग मुख्य है। लॉकडाउन के चलते पिछले कई दिनों से बिजली विभाग के कैश काउंटर बंद पड़े हैं। ऐसे में लोगों ने बिजली बिल ही जमा करना बंद कर दिया। ऐसे में कम आय के चलते कंपनी में कार्यरत और रिटायर 20 हजार से अधिक कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर संकट गहरा गया है। बता दें कि बिहार में लॉकडाउन के बाद रोज 4000 मेगावट से अधिक बिजली की खपत हो रही है। लोगों को बिजली देने का खर्च 7 रुपए प्रति यूनिट से अधिक है, लेकिन कमाई 4 रुपए ही प्रति यूनिट हो रही है। हालांकि, इस नुकसान का भरपाई राज्य सरकार अनुदान देकर करती है। बता दें कि राज्य सरकार ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए अररिया के जिलाधिकारी

कैसर का इलाज कराकर लौटे

तीन लोग निकले कोरोना पॉजिटिव

पटना | कोरोना वायरस के बीच मुंबई से इलाज कराकर पटना लौटे तीन लोगों की समझदारी ने दिखाई है। दरअसल, कैसर मरीज और उसके परिजन घर जाने की बजाए सीधे अस्पताल गए और कोरोना की जांच करवाने के साथ ही वहीं रहेंगे। यह जहां बाद में तीनों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। ये सभी लोग मुंबई से एबुलेस से पटना लौटे थे। उन्हें अशंका थी कि वह कोरोना वायरस की चेप्ट में आने की आशंका को देखते हुए खुद से ही पीएमसीएच में जांच कराने की मकसद से भर्ती हो गए थे। बता दें कि बिहार में शायद यह पहला मौका है जब असाध्य रोग से जुँझ रहे किसी मरीज और उनके परिजनों

पंचायत मुखिया ने पूरे गांव को खुद किया सैनिटाइज

रोहतास | रोहतास जिला के बीच प्रखंड के नरवर पंचायत की मुखिया सीता यादव जनसेवा में लगी हुई है। उन्होंने गांव में मजदूर नहीं मिलने पर पूरे गांव को सैनिटाइज करने का बीचा खुद उठा लिया है। पिछले एक सप्ताह से वे अपने पीठ पर सैनिटाइज का डब्बा बांधकर खुद से निटाइज कर रही हैं। सीता यादव के इस जज्जे को देखकर सभी लोग हतप्रभ हैं। पंचायत के कई गांव को अभी तक वे सैनिटाइज कर चुकी हैं। एक महिला जनप्रतिनिधि के इस तरह के कार्य से गांव के लोग खासे प्रभावित हैं। बता दें कि सीता यादव प्रतिदिन सुबह-सुबह अपने चेहरे पर मास्क लगाकर, घाथों में गत्स्य पहनकर खुद अपनी पीठ पर सैनिटाइज कर डब्बा लेकर निकल पड़ती हैं और गलियों में घूम-घूम कर सैनिटरज कर

उत्तरप्रदेश/बिहार

Web site : www.krantisamay.com & .in, epaper.krantisamay.com  www.facebook.com/krantisamay  www.twitter.com/krantisamay

दूटी 21 साल पुरानी परंपरा, सामूहिक विवाह में 501 जोड़ों का होना था विवाह, राष्ट्रपति का प्रोग्राम रद्द, लाखों शादियां टलीं

लखनऊ | कोरोना प्रकोप को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन की वजह से अक्षय तृतीया पर होने वाली शादियां कैंसिल करनी पड़ी हैं। और तो और, 5 मई को तो एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी शामिल होने वाले थे ले. किन अब यह कार्यक्रम भी स्थिरित हो गया है।

सामूहिक विवाह समारोह में 501 जोड़ों का विवाह होना था। अक्षय तृतीया पर इस बार न शहनाई गूंजी और न ही रोशनी की चकाचौंध दिखी। लॉकडाउन की वजह से लखनऊ में करीब 550 शादियां स्थिरित कर दी गई हैं। इस महामारी का असर कारोबार पर भी पड़ा है। कारोबारियों के अनुमान के मुताबिक, एक दिन में 150 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इसमें होटल, कैर्टर्स, वेडिंग प्लानर, सराफा, कपड़ा और कई उद्योग शामिल हैं। उल्लेखनीय सहालग शुरू होने के बाद सबसे ज्यादा शादियां अक्षय तृतीया के दिन ही होती हैं।

सोयना रेजीडेंसी होटल के मालिक और

लखनऊ होटल एसोसिएशन के पदाधिकारी राकेश

छाबड़ा पर्सी बताते हैं कि उनके यहां की सभी बुकिंग कैंसल हो चुकी हैं। हर साल केवल जगह की बुकिंग के लिए 50 हजार से 10 लाख रुपए तक लोग खर्च करते हैं। इसके अलावा खाना, सजावट और बाकी खर्च अलग है। निजी के अलावा नगर-निगम और एलडीए के बुकिंग वाले लेखाण्ड कल्पना मंडप की बुकिंग भी कैंसल हो चुकी हैं।

नगर-निगम मुख्य कर अधिकारी शशांक सिंह

बताते हैं कि शासन के आदेश के बाद सभी बुकिंग कैंसल कर दी गई है। अब लॉकडाउन के बाद उनका पैसा भी वापस किया जाएगा। कोई शादी की डेट आगे रखना चाहता है तो उसे वह तारीख भी दी जा सकती है। सीतापुर रोड निवासी ओंकार राय के बेटे की शादी भी। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन से दोनों तरफ से 5-5 लोगों के शामिल होने की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन नहीं मिली। दोनों परिवार की आपसी सहमति के बाद अब नवंबर में शादी होगी।

रामचन्द्र बग्धी वाले ने बताया कि तेज सहालग को देखते हुए उन्होंने मुगादाबाद से बिधियों तक का ऑर्डर दिया था। यही नहीं बैंड भी शाहजहांपुर, बरेली से बुलवाने की व्यवस्था तक कर ली थी।

शासीनगर दुग्गा मंदिर की ओर से बीते 21 वर्षों से अक्षय तृतीया पर 25 युवतियों का सामूहिक विवाह करवाया जा रहा है। संयोजक के राजेन्द्र गोयल ने बताया कि तेज सहालग को प्रस्ताव रखा था। पंडित सियाराम तिवारी ने बताया कि अप्रैल माह में 25, 26, 27 और मई महीने में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 23-24 शुभ मुहूर्त हैं। इसके बाद शुक्रावास्त हो जाएगा और विवाह के राजेन्द्र गोयल ने बताया कि अब नवंबर में सामूहिक विवाह करवाने का प्रस्ताव रखा गया है। पंडित सियाराम तिवारी ने बताया कि अप्रैल माह में 25, 26, 27 और 28, 29, 30 तक ही विवाह मुहूर्त हैं। एक जुलाई को हरिशंशनी एकादशी है। ऐसे में देवोत्थानी एकादशी पर चतुर्मास की समाप्ति पर ही विवाह 25 नवंबर से संभव हो सकेंगे।

बहू ने पहले परिजनों को दिया जहर फिर खुद ने भी खाया

एटा | एटा के एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत के मामला सामने आया है। बताया गया कि घर की बहू ने जहर देकर पहले सबको मारा और फिर खुद जहर खाकर आत्महत्या कर ली। एसएसपी ने बताया कि घर कलह चल रही थी। बहू रुड़की शिपट होना चाहती थी। इसी कारण इस वारदात को अंजाम दिया गया। जांच के दौरान पुलिस को घर से हारपिक

और सत्कास की डिब्बी भी मिली थी।

बताया गया कि कोतवाली नगर के मोहल्ला शुगार नगर में रिटायर्ड स्वास्थ्यकर्मी राजेश्वर प्रसाद पवारी पुत्र रामप्रसाद पचौरी रहते थे। उनकी पुत्रवृद्ध दिव्या पन्थी दिवाकर, नाती आरुष आरव (एक) रहते थे। कुछ दिन पूर्व बेटे की साली बुलबुल निवासी सोनर्ह निवासी सोनर्ह द्वारा प्रसाद की गई थी।

थी। दूध देने के लिए महिला आई थी। महिला ने गेट खटखटाया तो कोई आवाज नहीं आई। उसने अंदर झांककर देखा तो गेट के पास ही चारपाई पर दिव्या की लाश पड़ी दिखाई दी। यह देख वह चीख निकल गई। इस मामले की जानकारी आसपास के लोगों को दी गई।

चंदौली में फेड से लटक कर ग्रीन युगल ने दी जान

चंदौली | चंदौली में शादी के लिए परिवारों के तैयार नहीं होने पर एक भौमिका आई। उसने अंदर झांककर देखा तो गेट के पास ही चारपाई पर दिव्या गया। मौके पर एसएसपी सुनील कुमार सिंह, डीएम सुखलाल भारती, एडीएम प्रशासन विवेक मिश्रा, एसएसपी संजय कुमार, सदर विधायक विप्रिन वर्मा डेविड आदि रहे। यह देख वह चीख निकल गई।

पुलिस ने मामले की डॉग स्क्वार्ड आदि से जांच कराई है।

नोएडा के 40 हॉटस्पॉट में से 10 ग्रीन जोन घोषित, अभी 17 रेड जोन में

अभिनेत्री शिल्पा और उनके पति राज कुंद्रा ने टिकटॉक के अपने नए वीडियो में कुछ पंजाबी डांस मूव्स दिखाए हैं।

इस वीडियो के कैशन में उन्होंने लिखा है कि अगर आप खुश हैं, और आपको पता है तो बस बल्ले बल्ले करो। बता दें कि यह जोड़ी लॉकडाउन के दौरान कुछ मजेदार डांस के जरिए अपना वक्त काट रहा है और उनके फिटनेस का सीक्रेट सिर्फ डांस ही नहीं है। दरअसल, हाल ही में शिल्पा ने अपने और अपने परिवार का वर्कआउट शेड्यूल साझा किया था, जिसका वे अनुसरण करते हैं। पति राज और बेटे वियान के साथ वर्कआउट सेशन की झलकी पेश करते हुए शिल्पा ने लिखा था कि घैंचे कुछ दिनों पहले वियान के साथ थोड़ा वर्कआउट मस्ती किया था और फिर मुझसे पूरे वर्क। आउट वीडियो की मांग की गई थी। हालांकि मेरे पास वर्कआउट का पूरा वीडियो नहीं है, लेकिन मेरे आर्काइव से मुझे जो भी कुछ मिला है, वह मैं साझा कर रही हूं। मैं वास्तव में मानती हूं कि जो परिवार साथ में खाना खाता है, प्रार्थना करता है और एक साथ काम करता है, वह हमेशा एकजुट साथ रहता है!

मानुषी छिल्लर बोली मुफ्त दिए जाए सैनिटरी पैड

पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर ने राज्य सरकारों से वंचितों को दैनिक राशन के साथ ही सैनिटरी पैड बांटने का भी आग्रह किया है।

मानुषी ने कहा कि सार्स-कोविड-2 के कारण दिहाड़ी कामगारों के हाथों में धन की कमी के कारण वंचित महिलाओं को गंभीर जोखिम हो गया है। उन्होंने कहा कि घैंचे बहुत शुक्रगुजार हूं कि सार्स-कोविड-2 संकट के दौरान भारत सरकार द्वारा सैनिटरी पैड को एक आवश्यक वस्तु के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। हालांकि, हमें इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि महिलाएं, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर तबके से, मुफ्त में पैड प्राप्त कर सकें। मैं विभिन्न राज्यों की सरकारों से भी आग्रह करती हूं कि वे दैनिक राशन के साथ-साथ वंचितों को सैनिटरी पैड वितरित करने की कृपा करें। बता दें कि मानुषी इस साल के अंत में अक्षय कुमार के साथ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म 'पृथ्वीराज' से बॉलीवुड में कदम रखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

यामी ने स्कूल के पहले दिन की तस्वीर की शेयर

अभिनेत्री यामी गौतम ने हाल में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने स्कूल के पहले दिन की फोटो शेयर की है। जिसमें मैं वह ग्रेट्यूनिक में स्कूल का आईकार्ड लगाए पूरी तरह से स्कूल जाने के लिए तैयार हैं, इस फोटो के कैशन में उन्होंने लिखा कि स्कूल का मेरा पहला

दिन, मैं यकीन के साथ कह सकती हूं कि मुझे नहीं पता था कि यह कितना मायने रखता है लेकिन मैं यूनिफॉर्म में तैयार होकर उत्सा. हित थी और देखने के लिए बेसब्र थी कि मेरे मां पापा मुझे कहा ले जा रहे हैं, और मेरी यह जिज्ञासा हमेशा बनी रही। इसके साथ ही उन्होंने अपने फॉलोवर्स से जिंदगी के हर पल को जीने के लिए भी कहा। उन्होंने ने आगे लिखा, जीवन के हर पल को हमें उत्सा.

हित करने दें, कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह हमें कहां ले जाती है, बस विश्वास करो, इसे गले लगाओ और चलते रहो है शटैग घर पर रहें हैं शटैग सुरक्षित रहें।



हाल में बॉलीवुड अभिनेत्री जान्हवी कपूर ने एक फोटो साझा की है, जिसमें वे सूर्य को चूमती सी नजर आ रही हैं। जिसे उनके प्रशंसक और फॉलोअर्स बहुत पसंद कर रहे हैं। बता दें कि जान्हवी ने इंस्टाग्राम स्टारीज पर यह तस्वीर साझा की है। इस फोटो में, सूरज की किरणें उनके चेहरे की चमक में इजाफा कर रही हैं। हालांकि जान्हवी कपूर के बचपन का यह फोटो उनकी मां दिवंगत सुपरस्टार श्रीदेवी द्वारा कुछ साल पहले पोस्ट की गई थी। 2016 में श्रीदेवी ने ट्रिवटर पर जो तस्वीर पोस्ट की थी उसमें जान्हवी एक छोटी बच्ची के रूप में हैं। वह लाल बिंदी और एक सोने की चेन से खेलती हुई बहुत प्यारी लग रही हैं। वहीं, हाल ही में जान्हवी ने 2016 की फिल्म 'उमराव जान' के लोकप्रिय गाने 'सलाम' को री-क्रिएट किया था। जान्हवी इंस्टाग्राम पर जेपी दत्ता की फिल्म के गाने 'सलाम' पर कथक करती नजर आई। वहीं, अब जान्हवी 'गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल', 'रुहीअफज़ा' 'तख्त' और 'दोस्ताना 2' में दिखाई देंगी।

मारुति सुजुकी ने ऑल्टो के 10 को वेबसाइट से हटाया कार का स्टॉक गत दिसंबर में ही कर चुके थे खत्म

नई दिल्ली। अपनी ऑफिशल वेबसाइट से मारुति सुजुकी ने ऑल्टो के 10 मॉडल को हटा दिया है। इस कार को मारुति ने बीएस6 अपग्रेड नहीं किया था, जबकि कंपनी की बाकी कारें अब बीएस6 कम्प्लायंट हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कंपनी के ज्यादातर डीलर बीएस4 मारुति सुजुकी ऑल्टो के 10 का स्टॉक दिसंबर में ही खत्म कर चुके थे और इसकी बुकिंग भी बंद कर दी थी। बताया जा रहा है कंपनी ने मारुति ऑल्टो के 10 को बंद कर दिया है, परंतु मारुति सुजुकी ने ऑल्टो के 10 को बंद करने की अभी ऑफिशल घोषणा नहीं की है। ऑल्टो के 10 वाला 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन मारुति एस-प्रेसो, सिलेरियो और वैगनआर में भी दिया गया है। इन तीनों कारों में यह इंजन अब बीएस6 कम्प्लायंट है। ऑल्टो के 10 में यह इंजन पेट्रोल वर्जन में 23.95 किलोमीटर प्रति लीटर और सीएनजी वर्जन में 32.26 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का माइलेज देता था। मालूम हो ? कि साल 2010 में मारुति ऑल्टो के 10 को भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया था। 2014 में इसका फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च हुआ, जिसमें कार के लुक और फीचर्स में बड़े देखने को मिले।



पीएनबी ने कहा, आईएमपीएस फंड ट्रांसफर पर अब कोई चार्ज नहीं

नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र के दूसरे सबसे बड़े बैंक ने अपने लाखों ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। पंजाब नैशनल बैंक ने कोरोना के कारण जारी लॉकडाउन के बीच डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने और ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आईएमपीएस फंड ट्रांसफर चार्ज को माफ कर दिया है। बैंक के ट्रैटर के मुताबिक, पीएनबी के ग्राहक अगर इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग एप का इस्तेमाल कर

आईएमपीएस फंड ट्रांसफर करते हैं, तब उन्हें कोई चार्ज नहीं लगेगा। अब पीएनबी के ग्राहक आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई से अगर ट्रांजैक्शन करते हैं, तब यह

एचडीएफसी ने रिलायंस कैपिटल में 6.43 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी

नई दिल्ली। आगास रिंग कारोबारी एचडीएफसी ने बताया कि उसने रिलायंस कैपिटल के अपने पास गिरवी रखे शेयरों को शर्त के अनुसार अपने काम करते हुए उसकी 6.43 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है। एचडीएफसी लिमिटेड ने शनिवार को नियामकीय सूचना में कहा है कि कंपनी ने इन शेयरों को गिरवी रख कर उससे सामान्य व्यावसायिक तरीके से कर्ज लिए थे। कंपनी की ओर से प्रतिभूति ट्रस्टी ने इन



कुल कारोबार 18 लाख करोड़ का है। पूरे देश में इसके 11 हजार से ज्यादा ब्रांच और 13 हजार से ज्यादा एटीएम हैं।

शेयरों को एचडीएफसी के पास बंधक रखा था। इस कदम से एचडीएफसी लिमिटेड ने रिलायंस कैपिटल के 10 रुपये मूल्य वाले 25.27 करोड़ शेयरों का अधिग्रहण कर लिया है। इन शेयरों का कुल मूल्य 252 करोड़ है। एचडीएफसी ने कहा है कि इस संबंध में 27 मार्च को पहले ही जरुरी जानकारी दे दी गई थी और अब जबकि ये शेयर कंपनी के खाते में आ चुके हैं, एक बार फिर यह जानकारी दी जा रही है।

दुकानें दोबारा खोलने के नियमों में अधिक स्पष्टता की जरूरत : आरएआई

नई दिल्ली। खुदरा कारोबार करने वाली फर्मों के संगठन रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आरएआई) ने कहा कि गली-मोहल्ले में स्वतंत्र रुप से चल रही परचून की दुकानों को खोलने की अनुमति और स्पष्ट करने की जरूरत है। संगठन का कहना है कि इस आदेश की आधार की अलग-व्याख्या करने की सभी तबाना है। आरएआई ने कहा कि मौजूदा हालातों को देखकर लॉकडाउन के दौरान अनिवार्य वस्तुओं की बिक्री करने वाली खुदरा दुकानों को खोलने के अनुभवों का फायदा उठाकर सरकार को सभी तरह के खुदरा

स्वतंत्र रुप से चलने वाली दुकानों को खोलने की अनुमति शुक्रवार रात को दी। हालांकि दुकानदारों को अनिवार्य सावधानी बरतनी होगी, साथ ही ५० प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही काम करना होगा। गृह सचिव अजय भल्ला ने सरकारी आदेश जारी किया। इसके अनुसार नगर निकायों के द्वारा में आने वाले बाजार, बहुबांड और एकल ब्रांड मॉल इत्यादि तीन मई तक बंद रहेगी। आरएआई ने कहा, हमारा सुझाव है कि सरकार को जब सुरक्षित महसूस हो, उस दिन सामुदायिक दूरी नियमों के साथ सभी तरह के खुदरा क्षेत्रों को खोल दे। आरएआई ने सरकार से मॉल खोलने की भी अनुमति देने को कहा। आरएआई ने कहा, मौजूदा सरकारी आदेश की अलग-अलग व्याख्या की जा सकती है। इसके आसानी से अनुपालन के लिए इसे अधिक स्पष्ट बनाने की जरूरत है। बाजार परिसर में स्थित दुकानों सहित गली मोहल्ले में अलग-अलग

कहाँ, मौजूदा सरकारी आदेश की अलग-अलग व्याख्या की जा सकती है। इसके आसानी से अनुपालन के लिए इसे अधिक स्पष्ट बनाने की जरूरत है। बाजार परिसर में स्थित दुकानों सहित गली मोहल्ले में अलग-अलग

लॉकडाउन के बीच जियो का 'धमाका'! दूसरों का रिचार्ज कर ग्राहक कमा सकते हैं मुनाफा

नई दिल्ली। लॉकडाउन के बीच जियो बड़ा 'धमाका' करने जा रही है। रिलायंस जियो के ग्राहक अपने नेटवर्क पर अब दूसरे उपभोक्ताओं के अकाउंट को भी रिचार्ज कर सकेंगे, जिसके लिए उन्हें कैशबैक भी मिलेगा। जियो ने हाल ही में 'जियो एसोसिएट प्रोग्राम' की शुरुआत की है, जिसके तहत यूजर्स को अपने दोस्त, रिश्तेदार या करीबी का रिचार्ज करने पर कमाई करने का मौका मिलेगा। मिली जानकारी के अनुसार इसके लिए उन्हें करीब 4फीसदी का कमीशन मिलेगा। वे

रिचार्ज एक मोबाइल ऐप के जरिए कर सकेंगे। जियो ने ये कदम ऐसे समय में उठाया है जबकि कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन के चलते बहुत से लोग अपने फोन

पाए हैं, उन्हें लॉकडाउन के समाप्त होने तक इनकमिंग सुविधा मिलती रहेगी। इससे नासिफ कम कमाने वाले लोगों को फायदा होगा, बल्कि उन ग्राहकों को भी आसानी होगी जो लॉकडा। उन के चलते घर से बाहर जाकर रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो उपभोक्ता रिचार्ज नहीं करा

नकम दिया जा रहा है।



आईपीजीए ने पीएम-केयर्स कोष में 21 लाख रुपये दिए

नई दिल्ली। भारतीय दलहन एवं अनाज संघ (आईपीजीए) ने कोविड-19 संकट से निपटने के लिए पीएम-केयर्स फंड में 21 लाख का योगदान देने की घोषणा की है। संघ ने कहा, आईपीजीए ने पीएम-केयर्स कोष में 21 लाख रुपये देने का फैसला किया है। इसके अलावा यहमारे सदस्यों ने कोष में अलग से भी योगदान किया है। आईपीजीए इसके अलावा

कोरोना वायरस से निपटने में लगे लोगों तथा नियंत्रण वाले क्षेत्रों में फंसे प्रवासी मजदूरों और उनके परिवारों की भी मदद कर रहा है। इसके लिए वह 6,000 बैग उपलब्ध करा रहा है। एक राशन बैग में पांच किलो आटा, दो किलो दाल, एक लीटर पकाने का तेल, एक किलो चीनी और एक किलो नमक दिया जा रहा है।

बजाज प्लैटिना 110 की कीमत अब 59,802 रुपये

बाइक सिफर एक वेरियंट- डिस्क ब्रेक में उपलब्ध

नई दिल्ली। ऑटोमोबाइल कंपनी बजाज ऑटो ने बीएस6 कम्प्लायंट प्लैटिना 110 एच-गीयर प्रस्तुत की है? जिसकी कीमत 59,802 रुपये है। अब यह बाइक सिफर एक वेरियंट-डिस्क ब्रेक में उपलब्ध है, जबकि ड्रम ब्रेक वेरियंट को बंद कर दिया गया है। बीएस4 मॉडल के मुकाबले बीएस6 प्लैटिना 110 एच-गीयर की कीमत 3,431 रुपये है। बीएस4 डिस्क वेरियंट की कीमत 56,371 रुपये थी। अपडेटेड बजाज प्लैटिना 110 एच-गीयर में सबसे बड़ा बदलाव इसके इंजन में हुआ है। बाइक में पहले वाला 115सीसी, सिंगल-सिलिंडर, एयर-कूल्ड इंजन है, जो अब बीएस6 कम्प्लायंट है। अपडेटेड इंजन 8.44 एचपी का पावर और 9.81 एनएम टॉर्क जेनरेट करता है। इंजन 5-स्पीड ट्रांसमिशन से लैस है। बीएस4 वर्जन के मुकाबले बीएस6 इंजन का पावर थोड़ा कम है। बीएस4 वर्जन में यह 8.5 एचपी का पावर जेनरेट करता था। बीएस6 इंजन के अलावा प्लैटिना 110 एच-गीयर में कोई बदलाव नहीं हुआ है, यानी इसकी डिजाइन, साइक्ल एवं 9.81 एचपी का पावर और 9.81 एनएम टॉर्क जेनरेट करता है।



रियर में 110 एमएम ड्रम ब्रेक है। बाइक दो कलर ऑप्शन-ब्लैक और रेड में उपलब्ध है। इस कम्प्लायर बाइक में एलईडी डीआरएएल के साथ हैलोजन हेडलैम्प, ब्लैक अलॉय वील्ज और गियर शिफ्ट गाइड के साथ डिजिटल-एनालॉग इंस्ट्रूमेंट वलस्टर मिलते हैं।

एयरलाइंस की इकोनॉमी क्लास में किए जा सकते हैं कुछ संभावित बदलाव

नई दिल्ली। सोपल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देने के लिए एयरलाइंस में मिडिल सीट्स को हटाया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक

